

एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला वधियक लोकसभा में पारित

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन वधियक को लोकसभा ने दो-तर्हिई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। सदन ने राज्यसभा द्वारा वधियक में कथि गए संशोधनों को नरिस्त करते हुए संशोधनों के साथ 'संविधान (123वाँ संशोधन) वधियक, 2017' पारित कर दथि।

वधियक में मुख्य बदलाव

- एक दनि पूरव ही केंद्रीय मंत्रमिंडल ने अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार रोकथाम) अधनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी।
- लोकसभा द्वारा यथापारति तथा संशोधन के साथ राज्यसभा द्वारा लौटाए गए वधियक में पृष्ठ एक की पंक्ति एक में 'अडसठवें' के स्थान पर 'उनहत्तरवें' शब्द प्रतस्थापति करने की बात कही गई है।
- इसमें कहा गया है कि खंड तीन के पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3 का लोप कथि जाए तथा इसके स्थान पर राज्यसभा द्वारा कथि गए संशोधनों में पृष्ठ 2 और 3 पर नमिनलखित संशोधन अंतःस्थापति कथि जाए।
- संविधान के अनुच्छेद 338क के बाद नया अनुच्छेद 338ख अंतःस्थापति कथि जाएगा। इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पछिड़े वर्गों के लथि राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग नामक एक नया आयोग होगा।
- संसद द्वारा इस नमित्त बनाई गई किसी वधिके उपबंधों के अधीन आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। इस प्रकार नथुकुत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधिके संबंध में नथिम राष्ट्रपतिद्वारा अवधारति कथि जाएंगे।
- आयोग को अपनी स्वयं की प्रकरथि वनियमति करने की शक्ति होगी। आयोग को संविधान के अधीन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पछिड़े वर्गों के लथि उपबंधति सुरक्षा उपायों से संबंधति मामलों की जाँच और नगरिनी करने का अधिकार होगा।
- इसके अलावा आयोग पछिड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक वकिस में भाग लेगा और इस संबंध में अपनी सलाह देगा, जबकि पहले सरिफ सलाह देने की बात कही गई थी।
- संघ और प्रत्येक राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पछिड़े वर्गों को प्रभावति करने वाले सभी मुख्य नीति वधियक मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगे। इसमें पृष्ठ एक की पंक्ति चार में 2017 के स्थान पर 2018 प्रतस्थापति कथि जाएगा।

राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग

- वर्तमान राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। यह केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारति मंत्रालय के तहत चलने वाला वैधानिक आयोग है। 1993 में संसद में पारति कानून के तहत मौजूदा आयोग का गठन कथि गया था।
- इसका उद्देश्य अन्य पछिड़े वर्ग की सूची में नागरिकों को सम्मलित करने और हटाने संबंधी शकियतों को नपिटाने तथा उनकी जाँच के बारे में सरकार को सलाह देना है।
- अधनियम में प्रावधान है कि सरकार आयोग के परामर्श को मानने के लथि साधारणतया बाध्य होगी।